विश्व बैंक ईडीएफसी पर औद्योगिक विकास हेतु पूंजी लगाने को तैयार

विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रों को बेहतर बनाने एवं सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों हेतु सुविधाओं के नवीन निर्माण में निवेश

लखनऊ, 07 नवम्बर 2014

बहुपक्षीय ऋणदात्री संस्था, विश्व बैंक उत्तर प्रदेश में औद्योगिक अवस्थापना तथा सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों हेतु सुविधाओं के नवीन निर्माण के लिए पूंजी उपलब्ध कराने को तैयार है।

यह सूचना आज लखनऊ आई विश्व बैंक की एक टीम का नेतृत्व कर रहे, लीड अर्बन स्पेशियलिस्ट श्री बरजोर मेहता ने प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग (आईआईडी), श्री संजीव सरन से भेंट के दौरान दी। विश्व बैंक की एक तीन सदस्यीय टीम ने आज प्रमुख सचिव, आईआईडी को ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर (ईडीएफसी) के तहत चिन्हित **तीन उपक्षेत्रीय विकास केन्द्रों** के गहन आर्थिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट को परामर्शी क्राइसिल लि. ने **आगरा–फिरोज़ाबाद, कानपुर–लखनऊ–उन्नाव–औरैया तथा इलाहाबाद–वाराणसी उपक्षेत्रीय विकास केन्द्रों** में ***अवस्थापना एवं निवेश रणनीति*** विषय पर तैयार किया है।

इस रिपोर्ट में इन तीनों **उपक्षेत्रीय विकास केन्द्रों** में स्थाई औद्योगिक विकास हेतु अवस्थापना सुविधाओं में आवश्यक सुधारों को रेखांकित किया गया है।

बरजोर मेहता ने बताया कि प्रारम्भ में विश्व बैंक कानपुर–लखनऊ–उन्नाव–औरैया उपक्षेत्र पर विशेष ध्यान दे रहा है। **उन्होंने कहा** कि विश्व बैंक ईडीएफसी को तीन चरणों में फाइनेंस कर रहा है, जिसमें से दो चरणों पर कार्य शुरू भी हो चुका है। **श्री मेहता ने कहा**– "इस परियोजना के प्रति राज्य सरकार गम्भीरता व प्रतिबद्धता से प्रभावित हो कर विश्व बैंक ने यह निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश को दूसरे चरण में ही सम्मिलित किया जाए।"

विश्व बैंक ने फण्ड देने के लिए दो विकल्प दिए हैं। एक है 'विकास नीति ऋण' *(Development Policy Loan)*, जिसके तहत धनराशि तब अवमुक्त की जाती है जब सरकार पूर्व सहमति के आधार पर संरचनात्मक, वित्तीय व सामाजिक नीति–सुधार हेतु कुछ कदम उठाती है। इसका उपयोग अवस्थापना तथा अन्य प्रयोजनों हेतु किया जा सकता है। दसरे विकल्प, 'परिणाम हेतु कार्यक्रम' *(Programme-for-Results)* के अन्तर्गत पूंजी अवस्थापना विकास के निए नहीं, अपितु संस्थागत् सुदृढ़ीकरण, पर्यावरण संरक्षण, पुनर्स्थापना आदि के लिए प्रदान की जाती है।

सूचित किया गया कि प्रदेश में निवेश कार्यक्रम के तहत विश्व बैंक विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रों को बेहतर बनाने एवं सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों हेतु सुविधाओं के नवीन निर्माण में निवेश करने को तैयार है।

राज्य में औद्योगिक वातावरण को बेहतर बनाए जाने हेतु उठाये जा रहे महत्वपूर्ण कदमों पर बल देते हुए **प्रमुख सचिव, आईआईडी, श्री संजीव सरन ने कहा** कि उ. प्र. में लखनऊ, पूर्वी व पश्चिमी भाग में राज्य सरकार औद्योगिक क्षेत्रों के पुनर्निमाण हेतु पहले से ही कदम उठा रही है। **उन्होंने बताया** कि उद्योगों के संचालन व स्थापना की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु कई महत्वपूर्ण निर्णय शीघ्र ही लिए जाएंगे, जिसमें प्रमुख रूप से श्रम, वाणिज्यिक कर, प्रदूषण आदि से संबंधित प्रकरण है।

ज्ञात हो कि विश्व बैंक द्वारा हाल ही में ईडीएफसी के मुगलसराय–भाउपुर खण्ड पर 393 किमी लम्बी डबल लाइन विकसित करने हेतु 110 करोड़ डॉलर का ऋण प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है।

ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर की कुल लम्बाई 1840 किमी है, जो पंजाब में लुधियाना से प्रारम्भ होकर मुख्यतः उत्तर प्रदेश में खुर्जा से होते हुए पश्चिम बंगाल में दानकुनी तक जाएगा। इस परियोजना से उत्तर प्रदेश को अधिकतम लाभ होगा, क्योंकि इसका लगभग 57 प्रतिशत्, 1049 किमी लम्बा भाग उत्तर प्रदेश के 18 जिलों से होकर गुजरेगा, जिस पर 40 नये स्टेशन स्थापित करना प्रस्तावित है।

———————